6. The Appropriation (No. 2) Bill, 1982.

Sir, I also lay on the Table copies duly authenticated by the Secretary-General of Rajya Sabha, of the following six Bills passed by the Houses of Parliament during the last session and assented to since a report was last made to the House on the 30th April, 1982:—

1. The Pensions' (Amendment) Bill, 1982.

2. The Architects (Amendment) Bill, 1982.

The Pharmacy (Amendment) Bill, 1982.

4. The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 1982.

5. The Air Corporations (Amendment) Bill, 1982.

6. The Assam State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1982.

12.15 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

CONTINUOUS STRIKE BY TEXTILE WORKERS OF BOMBAY AND THE ACTION TAKEN BY GOVERNMENT

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

बम्बई के हजारों कपड़ा मिल मजदूरों की जनवरी, 1982 से निरंतर चली आ रही हड़ताल से उत्पन्न गम्भीर स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही "

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Sir, the House is aware that the strike in Bombay which has been declared illegal in most of the 60 Cotton Textile Mills, is continuing from the 18th January, 1982. The strike was called by an unrecognised union even though there already exista an agreement between the management and the representative labour union in the Cotton Textile Mills and which is valid upto 31st December, 1984. There was also no approach either to the State Government or to the management before the call to strike was given.

Both the State Government which is the appropriate Government to deal with the situation, and the Central Government have made continuous efforts to end the strike. The Chief Minister of Maharashtra has made it known that the State Government would look into all the legitimate demands of the workers on restoration of normalcy The Central Government has fully supported the stand taken by the State Government that all the legitimate demands of the workers should be resolved through the normal legal machinery.

2. Government is fully conscious of the hardships suffered by the workers. At the same time, Government is also aware of the loss of cotton textile production caused by this strike even though many mills have resumend partial working . Government has never stood on prestige in this issue and has repeatedly made it known to the workers that once normalcy is restored, expeditious steps should be taken to look into their genuine grievances and resolve them in a time bound programme.

3. As a result of several steps taken by the Central and State Governments many workers have returned to work. Government would now like to take some more steps with a view to demonstrating again that it has the larger interests of workers at heart.

4. With this end in view, Government has decided to set up a Committee, at

[Shri Bhagwat Jha Azad]

the national level consisting of representatives of (1) Central Trade Union Organisations, (2) Industry; and (3) Government. The Committee will have the following terms of reference:

(A) (1) Examine and report on the problems of textile mill industry workmen.

(2) Examine and report on the problems being faced by the textile mill industry including the urgent need to modernise the industry.

(3) The recommendations at (1) and (2) above will relate to the entire textile mill industry in the country.

(4) The Committee will give its report within a priod of one year and its recommendations relating to workmen will be implemented in a time-bound manner.

But, the Bombay Cotton Textile industry has been facing certain specific problems. Accordingly, the Committee shall give reports on:

(5) The problem of (i) Badli workers (ii) demand of workmen for House Rent allowance (iii) Demand of workmen for conveyance allowance. The Committee shall report on these matters within a period of two months and its recommendations shall be implemented at the earliest possible. Pending the receipt of the recommendation of the Committee on House Rent allowance and conveyance allowance, an ad hoc amount of Rs. 30 per month shall be paid to all workmen subject to adjustment.

(6) The demand of textile mill workmen of Bombay for grant of additional wages will be enquired into and reported on within a period of six months by the Committee and steps will be taken to implement them expeditiously.

(7) Such other problems as may be referred to the Commitee or as the Committee may like to report on shall be reported by the Committee to the Government within a period of one year.

The workmen who, in pursuance of this statement by Government resume work shall be granted by the management an amount of Rs. 650/- as an advance which shall be recovered in six equal monthly instalments, the recovery commencing six months after the grant of the advance.

No workman who returns to work shall be victimised for having participated in or joined the strike excepting those who had indulged in intimidation, violence or against whom criminal cases have been registered.

On behalf of the Government, I made this appeal to the striking workmen to return and resume work. By joining work they would help themselves and the industry and also serve the national interest.

श्री रामवतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस बात की अभी घोषणा की है, हड़ताल में शामिल ढाई लाख मजदूरों के प्रतिनिधि इसको मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे समस्या का समाधान फ़ौरन निकलने वाला नहीं है । मैं करीब पिछले छः माह से हड़ताल में शामिल ढाई लाख मजदूरों को हार्दिक बधाई देता हूं और सरकार की मजदूर विरोधी नीति के लिये निन्दा करता हूं ।

हड़ताल 18 जनवरी को शुरू हुई, आज इसका 173 वां दिन है । इतनी बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल आजतक हिन्दुस्तान में कभी नहीं हुई । 1928 में बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल जरूर की थी, लेकिन

उसकी मियाद 171 दिन थी । आज इस शानदार हड़ताल की मियाद 173 दिन हो गई है ।

मजदूर किसी के करिश्मे में आकर हड़ताल नहीं करते हैं, जैसा कि सरकार कहती है कि दत्ता सामान्त ने ऐसा करवा दिया है । मजदूरों के सामने कठिनाइयां हैं, उनका पे-रिवीजन का सवाल है, बदली मजदूरों को परमानेंट करने का सवाल है ।

इससे जब तक वह उत्तेजित और प्रभावित नहीं होंगें , हड़ताल नहीं होगी । हमारे आपके कहने से वह लोग हड़ताल नहीं करते हैं । अपनी कठिनाइयों की वजह से वह हड़ताल करते हैं ।

आज ढाई लाख मजदूर पूरी तरह से हड़ताल पर हैं और सरकार कहती है कि हड़ताल पूरी नहीं है । यह बात बताती है कि इनकी जानकारी पूरी नहीं है । स्टेट गवर्नमेंट की मजदूर विरोधी पालिसी है और उससे भी ज्यादा मजदूर विरोधी यहां का श्रम मंत्रालय है । जिसने बड़े बड़े इजारेदारों की मदद की है और मजदूरों को कुचलने की कोशिश की है । इसका सबूत हमारे आपके सब के सामने है । आप इस हड़ताल की व्यापकता देख लीजिये । हालत यह है कि आज तक मजदूर लड़ रहे हैं और सभी ट्रेड यूनियन वाले उनकी मदद कर रहे हैं । इनका राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, इंटक है, यह कहते हैं कि इन्होंने समझौता कर लिया है, 1984 तक समझौता चलेगा नहीं । क्या उनका कहीं कोई अस्तित्व है । मैं आपसे पूछना चहता हूं कि आप जबर्दस्ती इंटक की यूनियन को क्यों मजदूरों के सिर पर थोंपना चाहते हैं । क्या कारण है ? अगर वह उनके पीछे होते तो आज यह हड़ताल इतने शानदार तरीके से नहीं चलती । अगर आप यह समझते हों कि आप उन को दबा देंगे अपने दमन की चक्की चलाकर , तो आप भ्रम में हैं । अभी इसे 6 महीने हुए हैं जरूरत पड़ने पर मजदूर और भी 6 महीने की हड़ताल करने को तैयार हैं ।

इसलिये हडताल से जो नुकशान हो रहा है , देश की क्षति हो रही है, स्टेट्समैन के 6 जून के सम्पादकीय में लिखा है 650 करोड़ रुपये का नुकशान हो चुका है , 75 करोड़ रुपये फ़ारन एक्चेंज का नुकशान हुआ है । हर मजदूर का हर महीने 1200 रुपये का नुकशान हो रहा है इस तरीके से 600 मीटर कपड़ा बनना कम हो गया है । उसके उत्पादन में कमी आ गयी है । इसकी जवाब देही आप पर है , मजदूरों पर नहीं है । आज हमारे लोगों से हडताल कराने के लिये जिम्मेदार सरकार है । उसका यह काम है कि इस तरह की स्थिति पैदा न करे जिसे हमारी देश के अर्थतंत्र पर उसका बुरा असर पड़े और मजदूरों की कठिनाई बढ़े । लेकिन ऐसा न कर के यह मजदूरों का दमन कर रही है ।

19 अप्रैल को महाराष्ट्र बन्द हुआ । अभी कल महाराष्ट्र में 4 लाख दूसरे लोगों ने हड़ताल की , 5,000 औरतों ने डिमोंस्ट्रेशन किया ।

अगर इससे भी सरकार की आंखें न खुलें और उसे मजदूरों की मांगों के औचित्य का पता न लगे, तो उसकी बुद्धि की बलिहारी है भले ही वह मजदूरों की हितैषी होने का दावा करे और समाजवाद तथा लोककल्याणकारी राज्य की बात करे, लेकिन उसके दिल में टाटा, बिडला डालमिया, जैसे इजारेदारों के प्रति ज्यादा प्रेम है ।

मजदूरों को इतने दिनों तक हड़ताल करने की आवश्यकता न होती, लेकिन

[श्री रामावतार शास्त्री]

सरकार इंटक को मजदूरों पर लादना चाहती है और हड़ताल के जारी रहने का यही एक कारण है । मेहरबानी करके सरकार इस नीति को छोड़ दे । कोयला सैक्टर में भी वह यही कोशिश कर रही है कि इनटक के 50 प्रतिशत प्रतिनिधि रहेंगे । क्यों रहेंगे ? इनकी क्या हस्ती है ? जितनी हस्ती है, उतनी ही बात करें, ज्यादा नहीं । महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार की नीति के मूल में यही बात है कि इनटक को मजदूरों पर लादा जाये । लेकिन मजदूर इंटक को बर्दास्त नहीं करेंगे । सरकार की तरफ़ से कहा जाता है कि हम तो आई० एन० टी० यू सी० की मजदूर यूनियन से बात करेंगे । सरकार ने हड़ताल की स्थिति देख ली है कि कौन लोग किधर हैं । इस लिये उसे सब यूनियनों के साथ बात करनी होगी । जो मजदूर लडाई में शामिल हैं, अगर सरकार उनके साथ बात नहीं करेगी, तो यह समस्या कभी हल नहीं होगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shastriji, please place the demands of the workers.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I have already said. Pay revision is one of the most important demands.

इसके अलावा बदली मजदूरों का सवाल है, मजदूर विरोधी कानूनों को रद्द करने की बात है । मजदूरों की सब मांगें सरकार के पास मौजूद हैं । अगर सरकार उन सवालों के बारे में पाजिटिव एटीच्यूड नहीं अपनायेगी, नैगिटिव एटीच्यूड अपनायेगी, तो काम नहीं चलेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सचमुच यह चाहती है कि यह हड़ताल समाप्त हो और कारखाने फ़िर से काम करें । अभी कुछ समय पहले इस सदन में चर्चा हो रही थी कि फ़ौज के लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है ।, क्योंकि जो कपड़ा बम्बई में बनाया जाता था, वह नहीं बन सका । उन मिलों में कपड़ा बनें, फ़ौज के लोगों को मिले, देश की आर्थिक क्षति न हो और कपड़ा बनाने वाले मजदूरों की कठिनाइयां दूर हों, सरकार को इस दृष्टि से अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए ।

सरकार ने 1982 को उत्पादकता वर्ष का नाम दिया है और नारा लगाया है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए । इस हड़ताल के कारण 650 करोड रुपये का नुकशान आलरेडी हो चुका है । क्या यह प्राडक्शन बढ़ाने का तरीका है । मजदूर तो प्राडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार और मिल मालिक ऐसा नहीं चाहते । मिल मालिकों के पास पैसे की कमी नहीं है । वे पे-रिवीजन के मुताबिक पैसा देने की स्थिति में हैं । उन्हें फ़िनांशल इंस्टीट्यूशनज से माडर्नाइजेशन के नाम पर और दूसरे आधार पर पैसा मिल रहा है लेकिन वे मजदूरों को कुछ नहीं देना चाहते । अगर श्री झा इस बारे में चुस्त हो जायें, तो सब काम ठीक हो सकता है । अगर राज्य सरकार अपने मजदूर विरोधी चेहरे को बदल दे, तो तुरन्त रास्ता निकल सकता है, । 1981 में 25.5 मिलियन मैनडेज का लास हुआ था । अभी केवल 6 महीने में बम्बई में 26 मिलियन मैन डेज का लास हो चुका है । तो इस को क्या आप पसंद करते हैं ? इस का मतलब है कि आप पसंद करते हैं । देश की चिन्ता आप को नहीं है । देश के इजारेदारों की चिन्ता आप को जरूर है ।

मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि जो स्थिति अभी है आन्दोलन की, उस स्थिति को देखते हुए और देश की अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए क्या आप यहां इस सदन में यह एलान करने को तैयार है कि दत्ता सामन्त

समेत तमाम जितनी इस आन्दोलन में शरीक यूनियनें हैं उन के साथ बात करेंगे और आइ एन टी यू सो का रामनामी ओढ़ना छोड़ देंगे ? यह आप करेंगे तभी रास्ता निकलेगा । मेरा एकमात्र यही सवाल है कि आप की पालिसी बदलेगी या नहीं ? लोग अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर तक से कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो स्थिति अभी है इस स्थिति में एक ही साल्यूशन है कि आप एलान कीजिए कि आप तमाम इन यूनियनों से बात करने को तैयार हैं और बात कर के कोई रास्ता निकालेंगे ।

जो आप ने यह वक्तव्य दिया और कहा कि एक समिति बनाएंगे मजदूर उस से संतुष्ट नहीं हैं । उस को उन्होंने सुना है और पहले ही रिजैक्ट कर दिया है । जब उन्हें यह बात मालूम हो गई, आप को राज्य सरकार के जरिए, आप के जरिए यह प्रस्ताव उन के यहां पहुंच चुका, आप आज यहां बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस को नामंजूर कर दिया है । अगर आप नहीं मानिएगा तो आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में हड़ताल होगी । अभी कल महाराष्ट्र में हड़ताल हुई है, औरतों ने हड़ताल की फिर पूरे हिन्दुस्तान में हड़ताल होगी । 19 जनवरी के बन्द को तो आप जानते ही है उस से भी शानदार हड़ताल होगी और ऐसी स्थिति में फिर आप का चेहरा बेनकाब होगा । मजदूर के सामने तो आप का चेहरा बेनकाब पहले ही हो चुका है । हमारा यही कहना है कि अभी भी राज्य सरकार को सुबुद्धि आए और उस से ज्यादा आप को सुबुद्धि आए ताकि कोई रास्ता निकल सके ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगा कि जिस समय में बयान दे रहा था शास्त्री जी ने उस को सुना ही नहीं । एक शब्द भी उन्होंने इस बयान की बात नहीं कही । वही पुरानी बात दोहराते रहे (व्यवधान) . . . जरा बोलने दीजिए । आप अपनी बात कह चुके । मैंने जैसे आप को सुना है आप भी सुन लें ।

ऐसा लगता है कि पुरानी बात जो वह लिख कर लाए थे पढ़ने के लिए वही लिखा हुआ बयान पढ़ते रहे और पुरानी पुरानी कथा कहते रहे । हमने अभी यह कहा कि मजदूरों की कठिनाई को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि एक त्रिपक्षीय समिति बनायी जायगी जिस में केन्द्रीय मजदूर संगठन के प्रतिनिधि रहेंगे, एम्पलायर्स के प्रतिनिधि रहेंगे और सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे और यह समिति सम्पूर्ण टैक्सटाइल उद्योग की बात तो पीछे है, पहले बम्बई के सम्बन्ध में दो महीने के अंदर जो उनकी प्रमुख मांगे हैं जिस के बारे में अभी उन्हों कहा—बदली, हाउस रेंट, कन्वेयेंस एलावेंस, इन के बारे में दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और इसी से सम्बन्धित यह भी बात कही कि जब तक उन की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वही हाउस रेंट और कन्वेयेंस एलावेंस वगैरह के लिए 30 रुपया महीना उन को मिलना शुरु हो जायगा । यह उन्होंने नहीं सुना । यह उन के लिए कोई अर्थ नहीं रखता है ।

दूसरी बात मैं ने बतायी कि जहां तक उन के बेज बढ़ने का प्रश्न है, मैं ने कभी यह नहीं कहा कि इस में हम नहीं चाहते हैं, जो ऐग्रीमेंट है हम ने उस ऐग्रीमेंट की चर्चा सिर्फ की, हम ने यह नहीं कहा कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संगठन के थू ही काम हो । यह बयान तो सरकार ने दिया है, जिन प्रधान मंत्री की बात उन्होंने कही, उन्हीं प्रधान मंत्री की सरकार ने यह बयान दिया है और बार बार जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संगठन की बात कही जाती है, बाम्बे इंडस्ट्रियल ऐक्ट के अन्तर्गत यह प्रावधान पूरी तरह से है कि अगर मजदूर चाहें तो अपने किसी एसोसिएशन को, जिस को उन्होंने स्वीकार किया है उस को हटा सकते हैं और नया ले सकते हैं । किस ने मना किया आज तक दत्ता सामन्त जी को या श्रीमान् शास्त्री की आइटक यूनियन को कि वह जाय उस

[श्री भगवत झा आजाद]

कानून के अन्तर्गत और कहें कि यह नहीं है और और यह है । ये गए थे हाईकोर्ट में, दत्ता सामन्त जी, यह कहने के लिए कि यह ट्रेड यूनियन नहीं है लेकिन जब वहां पर रेजेक्ट हो गया तब इन्होंने कहा कि इसमें बोगस है तो उसके अनुसार अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, एकार्डिग टु दि हाईकोर्ट ।

लेकिन यहां पर जो प्रमुख प्रश्न है वह यह है कि स्ट्राइक को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं । सरकार ने अभी एक कदम यह उठाया है कि एक त्रिपक्षीय समिति की स्थापना की है जोकि दो महीने के अन्दर तीन विषयों पर अपनी रिपोर्ट देगी । विषय है—बदली, हाउस रेन्ट और कन्वेयेन्स एलाउन्स । जहां तक बेज की बात है, आपको मालूम है एन टी सी ने 112 मिल्स ले ली हैं और उन पर और दबाव है कि अन्य मिलों को भी लें । मतलब यह कि मिलें सिक होती जा रही हैं । आपको मालूम ही है कि मैं श्रम मंत्री हूं, कोई एम्प्लायर मंत्री नहीं हूं । शास्त्री जी, आपको जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन आपका भी जो चरित्र है श्रमिक वाला, वह भी मालूम है और जो मेरा चरित्र है वह भी मालूम है । हमारी सरकार हमेशा श्रमिकों के लिए ही काम करती रही है । आप हजार भाषण दें कि हम उनके विरोधी हैं, हम कुछ करते नहीं हैं और हम एम्पलायर के हैं, इससे कुछ नहीं होगा । मैं इतने उदाहरण दे सकता हूं कि आपने एम्पलायर्स की कितनी मदद की है जिसमें आप डूब जायेंगे लेकिन मैं उसको छोड़ता हूं । मैं यह कह रहा हूं कि आज सरकार ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया है कि एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई है जो तुरन्त दो महीने में श्रमिकोंकी तीन प्रमुख मांगों पर अपनी रिपोर्ट देगी । एक एड-हाक रिलीफ भी दी है 30 रुपए की जोंकि बेज के संबंध में है । सम्पूर्ण देश के स्तर पर जो टेक्सटाइल कमेटी बनाई गई है वह उस पर विचार करेगी, वह बम्बई के सम्बन्ध में 6 महीने में बताएगी और सम्पूर्ण देश के स्तर पर एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी ।

इसके अलावा हमने यह निर्णय भी लिया कि जो भी मजदूर काम कर आयेंगे, हम जानते हैं कि उनको कठिनाई है कि कैसे वे अपना काम शुरू करेंगे इसलिए हमने यह दिया है कि सभी मजदूरों को, बदली वालों को भी, जिन्होंने वर्ष भर काम किया है, 650 रुपया एडवान्स दिया जायेगा ताकि वे अपना घर सम्हाल सकें और काम प्रारम्भ कर सकें ।

मैं समझता हूं इतना अधिक करने के बाद भी अगर शास्त्री जी पुरानी बातों को ही दोहराते रहें तो उसका मतलब यह होगा कि यह कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, पोलिटकल यूनियन है । इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इस सरकार को बदनाम किया जाए और गिराया जाए । हमने कार्यकर्ताओं से, श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बात की है और इस निर्णय पर आए हैं और हमारा विश्वास है कि बम्बई के श्रमिक काम पर वापिस आयेंगे और अपना काम प्रारम्भ करेंगे । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं, नहीं आयेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : ठीक है, अगर ट्रेड यूनियन के तीन नेताओं के कहने पर ही चलता है तो यह पोलिटिकल है, ट्रेड यूनियन नहीं है । बहरहाल मेरा विश्वास है कि अब वे काम पर आयेंगे । इतनी अधिक सुविधायें देने के बाद श्री जार्ज फ़र्नान्डीस के "नहीं, नहीं" कहने से कुछ नहीं होगा ।

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): Sir, since my name has been mentioned, I have a right of personal explanation. Please allow me to make it now.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, my comment was on his remark *Nahim Ayenge.*

SHRI GEORGE FERNANDES: I am sorry, I have not been properly understood. While their demand is Rs. 6,000, he is offering them Rs. 650 as conveyance for six months. Then he is offering Rs. 30 as *ad hoc*—I do not know whow to define this Rs. 30. It is an insult to the worker and no selfrespecting worker would accept it. The most important thing is that the RMMS has to go. Unless it goes, the workers would not go back to work.

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki): The hon. Minister has stated that the strike was called by an unrecognised union and it is in violation of an agreement which exists between the management and the representative labour union in the cotton textile industry, which is valid upto 31st December, 1984. Now this strike has evidently proved that the so-called recognized union, the Rashtriya Mill Mazdoor Union, has not got the support of the vast majority of the textile workers of Bombay. It has been vindicated now, without an iota of doubt. Whether the Government is prepared now to negotiate and recognise the Union which have the backing of vast majority of workers, that is the main question. The recognition was given to a particular union under a peculiar Act of Maharashtra Government without obtaining the majority support of the workers. That is why the workers went on strike. So there is no meaning in saying that they have violated the previous agreement, an agreement which will be valid up to December 1984. So, my request to the hon. Minister is to negotiate with the real representatives of the workers. About 2,30.000 workers are on strike, and this is the longest strike in the history of textile industry in India. In 1928 the textile workers of Bombay had gone on strike for about 171 to 175 days. Now, this strike has surpassed that strike so far as the duration of strike is concerned. Some 25,000 to 30,000 workers started their strike on October 19, 1981. Subsequently some 25,000 to 35,000 workers went on strike for changing the agreement on bonus. Now more than 250 days have passed. What the Government has been doing all these days? The hon. Minsiter has come before us with a long statement now. But where was he for all these long days? Was he not reluctant to intervene in the strike earlier?

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is putting the question - 'Where was he?'

SHRI M. M. LAWRENCE: The policy followed by the Government of India is to suppress and subjugate the mass of workers not only in the textile industry, but in all spheres of production. If the workers go on strike for a genuine cause, they try to get the strike prolonged as long as possible to starve the workers and thus surrender them. This is not good for a government, a government which claims to be a modern democratic government, a government which claims for standing for the down-trodden and toiling masses. In fact, they are for the mill magnates, for the mill-owners, for the monopolists, for suppressing and subjugating the working class.

Recently the Maharashtra Chief Minister attended a meeting of Rashtriya Mill Mazdoor Sangh activists in INTUC office and some of the Maharashtra Congress (I) M.L.As. were also present in that meeting. He called upon the M.L.As to mobilise the workers against the strike and he asked them thosa ko thosa in Marathi, which means blows for blows, eyes for eyes. The question is: Whose eyes the Maharashtra Chief Minister wants and for whom and against whom he has called upon to mobilise ? Against the workers. And for whom? For the same mill-owners.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Lawrence, please conclude. Put a straight question to the Minister.

SHRI M. M. LAWRENCE: I want to ask: How much loss of production and wages of labour has taken place due to this strike?

[Shri M. M. Lawrence]

How much excise duty the Central Government have lost so far?

How hard hit have been the peasantry because of strike, affecting the price of raw cotton?

Taking into account all these facts will the Government take immediate steps for a negotiated settlement? The Minister in his statement has laid down certain conditions. He said that Government never stood for prestige. Was the Government sleeping all these days? Was it not a prestige issue for them? Had it not been so he would never have said:

> "once normalcy is restored, expeditious steps would be taken to look into their genuine grienvances."

The Minister in his statement has claimed that many workers have returned to work. How much is 'many workers'? Only six or seven per cent workers have gone for work. Even then mills are not functioning. Vast majority of workers are continuing the strike even though they are being intimidated by C.R.P., State Government police and the goondas supported by the mill owners as well as the so-called recognised Rashtriya Mill Mazdoor Sabha.

In the statement it has been stated about the formation of Committee to look into

> "The problem of (i) Badli workers (ii) demand of workmen for House Rent allowance (iii) Demand of workmen for conveyance allowance.
>
> The committee shall report on these matters within a period of two months and its recommendations shall be implemented at the earliest possible. Pending the receipt of the recommendation of the Committee on House Rent allowance and conveyance allowance, an *ad hoc* amount of Rs. 30|- per month shall be paid to all workmen subject to adjustment."

Rs. 30/- is a meagre amount The workers are not begging from the Government or the mill owners. They are labouring. They are sweating. They are spending their blood and getting wages for the labour that they put in. Is the Government prepared to give them an interim relief?

About victimisation it has been stated:

> "No workman who returns to work shall be victimised for having participated in or joined the strike excepting those who had indulged in intimidation, violence or against whom criminal cases have been registered."

This is so elastic. Any kind of interpretation can be given by the bureaucrats, mill owners, police officers and the ministers as well to victimise the workers.

My request to the Government is to take earnest and honest steps to settle the issue by revising the wage structure, by revising the bonus agreement and to give interim relief immediately.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I have explained the provisions that we have been able to do in this statement. We have done maximum for the workers. We have given them the best and I am sure, in spite of these talks here, they will come back to work. If a friend like Shri Lawrence can make such a wild statement that the Chief Minsiter said- 'fist for fist, eyes for eyes, tooth for tooth, the least I can say is that on such a cock and bull story they prosper and thrive. We never believe in this principle of cock and bull storey. We are for the relief to workers. We have tried our best and as is indicated in this statement Government has done its best. We have never said that this Rs. 30|- is enough or is for an increase in the *ad-hoc* wage. We have just said that it will be till we get the report within a period of two months. In the Committee the workers representatives will be there. Pending the receipt of the recommendation of the Committee on House Rent allowance and conveyance allowance, and *ad hoc* amount of Rs. 30 per month shall be paid. This amount is just being given by the Government.

For the other part, we have said that *ad hoc* increase of wage is a question

which has All-India perspective and can be gone into in a little detail by this Committee which has to submit the report within six months. The statement of Mr. Lawrence once more demonstrated that some of the trade unions in this country are not for the labour or workers but they are political unions, just to have a stick against the Government. I do not believe in this, Sir. This Government is always for the labour and it has amply demonstrated it. The workers have got confidence in the Government.(*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must also keep quiet. You must be tolerable. There are always two sides on any issue.

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him reply. You allow him to reply.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Whereas some hon. Members have made all wild allegations and travelled all over the world including the labour world, I am only saying that we have amply demonstrated that the workers of this country have got confidence in this Government led by Madam Prime Minister. If you see the industrial production which was minus 1.4 percent during the last two years, it has now gone up to 10 per cent. The agriculture production is 130 million tonnes. This should not have been done by the trade union leaders or the political leaders without the cooperation of the workers.

Now the increased production demonstrates amply that the workers have faith in this Government and we have love for them. Some hon. Members mentioned about trade unions but they are political unions.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): The R.M.S. is very unpopular in Bombay. You must know that. (*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTW (Calcutta South): Sir, every issue is a political issue.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, every isue is a political issue.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Including your ruling.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This trade union in Bombay is so unpopular they cannot enter the textile area. He did not know about it.

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय शास्त्री जी बड़े गौरव और बड़ी शान के साथ फ़रमा रहे थे कि इस हड़ताल को 173 दिन हो गये हैं जैसे मज़दूरों और देश के लिए वे बड़ा अच्छा काम करा रहे हैं।

मान्यवर, हमारा देश ग़रीब है और ग़रीबों की जो स्थिति है, मज़दूरों की जो स्थिति है, वह मैं समझता हूं, यह सदन और यह देश पूरी अच्छी तरह से जानता है। हकीकत यह है कि जो लोग इस हड़ताल को चलवा रहे हैं, इस को बढ़ावा दे रहे हैं, उन का मज़दूरों के हितों से दूर का भी कोई संबंध नहीं है। केवल तथाकथित नेता अपनी नेतागिरी को कायम रखने के लिए मज़दूरों को गुमराह कर रहे हैं, जिस से मज़दूरों का और देश का, दोनों का ही नुकसान हो रहा है। 4 करोड़ रुपये प्रति दिन की हानि हो रही है और करीब 600,650 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का जो निर्यात होने वाला था, वह भी रुक गया है। बम्बई में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिस का असर बम्बई में ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ रहा है। मैं यह मानता हूं कि मज़दूरों की समस्याएं हैं और समस्याएं हो सकती हैं। उन पर विचार करना चाहिए और उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए।

[श्री चन्द्र पाल शैलानी]

मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और माननीय श्रम मंत्री झा साहब ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समिति गठित की है। उसके सामने मजदूरों के लिए कार्यक्रम हैं और वह अपनी रिपोर्ट भी देगी उस रिपोर्ट के आधार पर मजदूरों की समस्याओं को हल किया जाएगा। हमारी सरकार और हमारे नेता चाहते हैं कि मजदूरों की समस्याओं को सुना जाए, उन्हें देखा जाए। लेकिन यह सब काम कानूनी तरीके से और कानूनी दायरे में होना चाहिए। बहुत से मजदूर काम पर आ रहे हैं लेकिन दत्ता सामंत के लोग उनको काम पर आने से रोकते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मजदूरों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लिया जाए और उन्हें दूर करने के उपाय किये जाएं। लेकिन जिस गुण्डागरदी से लोग मजदूरों को डराते हैं, धमकाते हैं, उस गुण्डागर्दी के सामने सरकार को नहीं झुकना चाहिए और किसी कीमत पर भी नहीं झुकना चाहिए।

इस हड़ताल से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को कुछ फ़ैसले लेने चाहिए, कुछ कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे कि यह स्थिति समाप्त हो। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक जो कार्यवाही की गयी है उस से यह पता चलता है कि हमारी सरकार इस मामले में कितनी दरियादिल है। स्वयं मुख्य मंत्री ने दिल्ली आ कर के इस के सम्बन्ध में केन्द्रीय नेताओं से बातचीत की है और प्रधान मंत्री जी से भी बात की है। यह हड़ताल समाप्त होनी चाहिए (व्यवधान)

अब मैं अन्तिम शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हड़ताल चल रही है, और जो मजदूर काम पर आना चाहते हैं, सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए। काम पर आने वाले लोगों को कोई परेशान न करे, इसके लिए सरकार को सही व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार के नेता और भाड़े के आदमी उनको परेशान करते हैं और उनको काम पर नहीं आने देते हैं।

इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय कुछ आशा की किरण लगी। शैलानी ऐसे सदस्य हैं कि जिन्होंने कि बात को समझा। इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो सही स्थिति को समझते हैं और उसके लिये किये गये उपायों को रचनात्मक दृष्टि से देखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें कि मीनाक्षी नजर आती है।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): No question was asked. Mr. Shailant never asked a single question. What is he replying to? He did not ask any question. Why should he reply?

SHRI GEORGE FERNANDES: Mutual admiration.

SHRI INDRAJIT GUPTA: What question is he replying to?
आप किस का जवाब दे रहे हैं

श्री भागवत झा आजाद : आपने उनके प्रश्न को नहीं समझा है, मैंने समझा है और उन्हीं का मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने यह प्रश्न किया है कि क्या गुण्डागर्दी और जोरजबरदस्ती से किये गये काम का आप समर्थन करेंगे? मैं जवाब दे रहा हूं कि नहीं करेंगे। गुण्डागर्दी की जायेगी या जोर-जबरदस्ती करके किसी को भड़काया जाएगा तो उस का समर्थन सरकार नहीं करेगी।

दूसरे उन्होंने पूछा कि जो घोषणायें हमने की हैं, क्या उन पर अमल होगा? मैं कहता हूं उन पर अमल होगा?

आपको ये प्रश्न समझने में दिक्कत हो गई ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मुझे आशा की किरण नजर आयी । मैं अपने माननीय मित्रों से अपील करता हूं कि वे अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ें और वर्कर्स को न भड़कायें। सरकार मजदूरों के लिये अच्छे बराबर उपाय कर रही है लेकिन इन्होंने यह निर्णय कर लिया है कि जो कुछ हो वह इन्हीं के जरिये से हो। चाहे कितना भी अच्छा काम हो, वह इनके द्वारा हो । यह अच्छा नहीं है ।

13.00 hrs.

अच्छा काम तो अच्छा होता है, चाहे मैं कहूं या आप कहें और बुरा काम बुरा होता है, चाहे मैं कहूं या आप । कमेटी बनी है, हमने कुछ निर्णय लिये हैं और जल्द से जल्द कार्यवाही होगी । मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहता हूं और किसी से नहीं कहूंगा, कृपा करके आप इन लोगों से अलग हो जायें, जो लाल रंग वाले हैं ।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : मैंने तो अलग कर दिया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: When you mentioned Dr. Subramaniam Swamy's name, immediately he gets up and tries to get a chance also.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: But he spoke nicely, not the other way. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is coming closer to you now.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I do not know; if, gradually, he changes his ideas and becomes a socialist, he will come nearer to me.

इसलिये मैं कहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं, इन्द्रजीत जी हैं और सबसे मैं निवेदन करता हूं कि मजदूर काम पर जायें, जिन बातों को वे कह रहे हैं उनका निश्चित ही हल निकाला जायेगा, इस बात के लिये सरकार कृतसंकल्प है। (इति)

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाम्बे में टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को इतने दिनों तक स्ट्राइक पर रहना पड़ा है । इसके पीछे क्या बात है यह तो ट्रेड यूनियम लीडर्स ही जानते होंगे और सरकार जानती होगी, लेकिन जहां तक मुझे मालूम दिखाई पड़ता है और जो थोड़ी कामन सेंस हम लोगों में है, उससे यह लगता है और जो थोड़ा यह लगता है कि टेक्सटाइल मिलों की जो हालत है, जो हालत पूरे देश में चल रही है, जिस स्थिति से टेक्सटाइल इण्डस्ट्री इस समय गुजर रही है, उसमें यह एडवाइजेबल नहीं था कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स हड़ताल पर जाते । मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार ट्रेड यूनियन लीडर, चाहे वे गुप्ता जी हों, चाहे फर्नाण्डिस साहब हो या कोई भी हों, ऐसी स्थिति में कोई भी मिल मजदूरों को यह सलाह नहीं देता कि वे हड़ताल पर जायें और मैं समझता हूं कि उन्होंने सलाह नहीं दी । वहां एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है और ट्रेड यूनियनिज्म को गुण्डाइज्म ने अपने हाथ में ले लिया है और पूरे के पूरे वर्कर्स गुण्डाइज्म के बल पर काम पर आने से रोक दिये गये हैं ।

आज शास्त्री जी जैसे हमारे मित्र या दूसरे मित्र यह मजबूर होकर कह रहे हैं कि हड़ताल चलनी चाहिये, ताकि कहीं वे पीछे न छूट जायें, इसलिये उनको मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, लेकिन अपने दिल के अन्दर वे अच्छी तरह से

[श्री जैनुल बशर]

समझ रहे हैं कि हड़ताल ठीक नहीं थी। हड़ताल को नहीं चलना चाहिये था।

हड़ताल के पीछे कौन से एलीमेंट्स हैं और किस तरह से यह हड़ताल चल रही है, इस बात को आपको सही रूप में बोलना चाहिये। अगर आप लोग सही बोलते, ट्रेड यूनियन लीडर्स सही बोलते तो यह हड़ताल इतने दिनों तक नहीं चलती। आप बताइये कि क्या आज टैक्सटाइल मिल्स की यह हालत है कि वहां पर हड़ताल चल सके?

श्री रामावतार शास्त्री : हां है।

श्री जैनुल बशर : (गाजीपुर) शास्त्री जी यह बात कह सकते हैं, लेकिन गुप्ता जी नहीं कह सकते। हड़ताल का एक समय होता है कि कब हड़ताल होनी चाहिये और हड़ताल से ज्यादा मांगें कब मनवाई जा सकती हैं और कब नहीं।

बहरहाल उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय श्रम मंत्री जी ने कुछ घोषणा यहां की है और वह घोषणा इस हड़ताल को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगी। श्रम मंत्री जी ने केवल वर्कर्स की मांगों को ही ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टोटेलिटी में लिया है। वर्कर्स की क्या मांग है, उनको क्या फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस स्थिति से गुजर रही है—इन सारी बातों के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। बम्बई की जो विशेष समस्या है उसको हल करने के लिए बहुत जल्दी समिति का गठन किया जाएगा और छः महीने का समय दिया है। इससे मैं समझता हूं कि हड़ताली मजदूरों को हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री जी ने टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल के संबंध में कामर्स डिपार्टमेंट तथा दूसरे डिपार्टमेंट्स से भी सलाह मश्विरा कर लिया है और उसके बाद उन्होंने वह घोषणा की है कि उनको समझदारी से काम करना चाहिये और हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिये। आजाद जो जब से श्रम मंत्री बने हैं उनकी बराबर यह कोशिश रही है कि श्रमिक के हित में काम किए जायें। आज इसके बारे में घोषणा करके उन्होंने दिखा दिया है कि वह मजदूरों के हितैषी हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी समस्याओं को वह हल करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो घोषणा उन्होंने की है, उसको करने से पहले क्या उन्होंने श्रमिकों की ट्रेड यूनियनों से, उनके रिप्रिजेंटेटिव्ज से बातचीत कर ली है और कर ली है तो किस-किस से बात कर ली है और इस बातचीत का क्या असर हुआ है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। मैं पहले कह चुका हूं कि इस प्रकार की घोषणाओं के बावजूद अगर वर्कर काम पर आना चाहते भी हैं तो उनको गुंडे तत्व रोकते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसके बारे में भी व्यवस्था की है कि ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन से ठीक प्रकार से डील किया जाना चाहिये और ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिये जिससे श्रमिकों में डर और भय की भावना न रहे और वे अगर काम पर वापिस आना चाहते हैं तो आ जाएं। वर्ना जैसा मैंने पहले कहा है लाख घोषणायें आप

करें अगर गुंडाइज्म से निपटने की आप में शक्ति नहीं है और आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहां की हड़ताल समाप्त नहीं हो सकती है । कितनी भी सुविधायें आप दे दें कुछ नहीं होगा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल मिलों की हड़ताल के कारण प्रोडक्शन का कितना नुकसान हुआ है, मिलों को कितना हुआ है और सरकारी खजाने को कितना हुआ है ?

श्री भागवत झा आजाद : जिस बात को मैं ठीक से नहीं कह पा रहा था उसको माननीय सदस्य ने अपने पहले भाग में कह दिया है । हमारे कुछ विरोधी दलों में मित्र बैठे हुए हैं। वे भी नहीं चाहते थे कि यह हड़ताल हो । लेकिन लाचारी में उनको भी अब उनके साथ चलना पड़ रहा है । एक पाइप पाइपर आदमी आया उसने कहा पीछे पीछे चलो और सब के सब पीछे चल पड़ते हैं । "कभी ऐसा भी होता है जमाने की रवानी में कि राहजनों का अमीरे कारवां कहना पड़ता है ।" माननीय सदस्य ने श्रम मंत्री द्वारा बात करने की बात कही है । अगर मैंने अब तक सब से बात नहीं भी की है तो भी काम अच्छा किया है या बुरा किया है, यह आपको देखना चाहिये । अच्छा काम मैंने किया है। बुरा तो नहीं किया है । श्रमिकों के काम पर आने के लिए अगर मैंने अखिल भारतीय स्तर पर कमेटी बनाई जिस में सैंट्रल ट्रेड यूनियंज के लोग भी रहेंगे और वह छः महीने में या दो महीने में रिपोर्ट दे देती है और अगर हमने यह काम उनकी भलाई के लिए किया है और अगर नहीं पूछा है तो यह कोई गुस्ताखी तो नहीं की है । काम तो गलत नहीं किया है ।

आपने पूछा है कि कितना घाटा हुआ है । एक मित्र ने कहा छः हजार करोड़ होगा या साढ़े छः हजार करोड़ होगा । अब आप दिमाग की उड़ान को देखिए । किसी ने कहा ढाई सौ करोड़ होगा । कितने करोड़ का हुआ है । यह तो वास्तव में कामर्स मिनिस्टरी ही बता सकती है । किसी वक्त पूछेंगे और बता देंगे । घाटा हुआ है इसको ब्यान में भी मैंने स्वीकार किया है । अपनी तरफ से एक अच्छा उपाय निकालने की मैंने कोशिश की है ताकि श्रमिक बन्धुओं को काम पर आने की सुविधा हो और वे आ जायें ।

कमेटी का जहां तक सवाल है उसको हम जल्दी से जल्दी बनायेंगे । जल्दी का जो अर्थ है उसी अर्थ में इसको जल्दी बनायेंगे । उससे भी अधिक अर्थों में हम इस समस्या का निपटारा करने की भी कोशिश करेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ananda Pathak. Your work is now easy because all the previous Members have already spoken.

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling): Sir, I congratulate the workers who are conducting the strike for the last six months in the textile mills. Before me, one hon. Member said about the goondagiri of the workers. But, I would like to say that the workers never resorted to goondagiri but it is the Rashtriya Majdoor Sangh who are alluring the workers, subjugating and compelling them to go back to their work. I cannot understand how he can say that the workers were resorting to the goondagiri. I am very sorry to read this statement circulated by the hon. Minister where I find that Government is supporting the 'anti-workers' policy. They are trying to allure the workers by paying them some paltry sum and by asking them to go back to their work.

Why not the Government, instead of supporting the employers who are offering this paltry amount and alluring the workers to go back to work, come forward to call all the leaders of the trade unions for

(Shri Ananda Pathak)

a round-table conference to discuss this matter straighway and solve their problems? Instead of doing this, the Government is only taking the side of the employers. Moreover, the strike was undertaken by the workers on a fundamental issue. The workers are fighting for their right of collective bargaining. This is their right to strike work. Their demand is for the wage revision, bonus and improvement of their working conditions. I do not want to go into all the details of it.

Sir, the hon. Minister says that he is sympathetic about the demand of the workers. If that is so, why don't you call all the represnetatives of the workers for a round-table conference? Instead, he only gave a repeated call to the workers to go back to their work. You will set up a Committee only after they go back to their work. All this can be done after normalcy is restored. At least you may call all the leaders of the striking workers and discuss their problems.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You put your questions.

SHRI ANANDA PATHAK: What I say is that they are only trying to subjugate the workers and compel them to go back to their work. The workers are asking for the Provident Fund advance which is provided for under the Provident Fund Scheme. All the workers of the mills and undertakings which are closed for more than sixty days can apply for such an advance. They can take that advance. They are not allowing even that right of the workers to take this advance.

The Minister has already mentioned that the agreement is there which is valid upto 31st December, 1984. But, Sir, the situation has radically changed in the meantime. The cost of living has gone up; prices are spiralling up. The workers have every right to demand for the review of the agreement. The Minister is saying that this agreement which is already there is valid upto 31st December, 1984. Sir, the Government has also stated that they have been making a continuous effort to end this strike. I would like to know what concrete steps they have taken. I do not find any mention of it in the Statement and the hon. Minister in his speech on the Floor of the House has also said nothing about it. Again it is written here that Government would not stand on any prestige. If that is so then why don't they call the leaders of the striking workers and settle the disputes across the table. I would like to urge that Government should take initiative and all the trade unions excepting RMMS which is opposing the strike should be called and the matter may be discussed in a congenial atmosphere. Thereafter the Government may convene tripartite meeting and discuss all the problems and accept all their reasonable demands. Thereafter the Committee may be set-up—which the Government is considering to set up—to go into the details. In this way the problems can be solved and, I hope, the hon. Minister will respond in a positive way to all my suggestions.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Mr. Deputy Speaker, Sir, all through the speeches of the hon. Members who have put the Questions there have been three trends. One is the chosen words that they have used, viz., our is a antilabour Government, we want to divide the labour, subjugation, harassment, etc. All these are the chosen words. All these chosen words are being used because there is a concerted policy since January 1982 to speak against the Government. Sir, when we call the productivity council meeting they would not come whereas they say that they want to help production. The second point is that they have made only one demand, namely, you call all the trade unions and then decide.

Sir, I have already said that I do not want to infringe upon the rights of the workers either in their collective bargaining or in their right to choose their representatives. Some hon. Members have said that RMMS has got no representative character. All right. They are welcome to say that. Now, the Bombay Industrial Relations Act has enough provision under it to dethrone one whom the workers do not like and bring in those whom they like. Let them do it and I will call them who are chosen. I will have no hesitation to talk to them. But this coglomeration of so many so-called trade unions not having following of workers or are following Datta Samant, Sir, I am not in a position to call them.

The only demand is that I should call them and talk to them and then whatever has been said by me will become good.

Sir, I would like to say again that I do not want to infringe upon the rights of the workers. Let them choose their representatives and I will talk to them. Sir, Mr. Pathak wanted to know about the concrete steps from me. Sir, this statement as given the concrete steps one after the other. The greatest concrete step is that of an All India Committee of tripartite nature of representatives of workers, employers and Government to sort out textile issues all over the country and particularly that of Bombay. Is that not a concrete step? Well, Sir, I can give facts and figures. I cannot give understanding. I am sorry to say this, Sir. It is most unfortunate that some of the trade unions are still harping on their old song and want them to be called. I hope that will still go through my statement, ponder over it. I hope they will advise the workers to resume work. I appeal to the workers to come and resume their work. I appeal to them to allow this committee to function. I request them to represent whatever they want before this Committee, through their chosen representatives, whomsoever they choose, or, as they like, through any of their representative worker, etc. Let them put their own demands before it. I am sure that in the interest of themselves, in the interests of the industry, in the interests of the country they will come forward and resume work.

SHRI INDRAJIT GUPTA: May I seek a clarification? I seek this clarification from you, Mr. Deputy Speaker. For the last 45 minutes we have been discussing this subject. You are an old trade unionist.

MR. DEPUTY-SPEAKER: On this subject, he knows better than me.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Only I want to know one thing. Because, everybody wants a settlement no doubt, he has proposed this committee and he says that within 2 months they will go into the Bombay matter, and give their decision. But it is a tripartite committee. Mill owners will be there. Unions will be there. Government will be there. You know it. In such a committee, if it is not possible to come to an agreed decision, unanimous decision, as it is very likely, than, what will happen? He has not suggested anything. What will happen in such a case? Suppose they cannot agree on a unanimous decision, what will happen?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I seek a clarification. I am not asking a question. Please listen to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please. Now, Legislative Business. Mr Singh Deo. I have allowed him on behalf of Mr. R. Venkataraman.

13.22 hrs.

CANTONMENTS (AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K P. SINGH DEO): On behalf of Shri R. Venkataraman I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cantonments Act, 1924.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cantonments Act, 1924."

The motion was adopted.

SHRI K. P. SINGH DEO: I introduce the Bill.

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): Sir, I think the Commerce Minister would like to make a statement...

MR. DEPUTY SPEAKER: No, no. Order please. The House stands adjourned for lunch till 14.25 hours.

*Published in Gazette of India Extra- ordinary Part-II Section 2, dated 9-7-82.